बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 230 ● नई दिल्ली ● शनिवार 13 सितम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

यमुनानगर में बुजुर्ग की हत्या, प्लॉट में बुरी हालत में मिला शव, 15 दिन पहले पोते का भी हुआ था मर्डर

यमुनानगर । यमुनानगर के कस्बा रादौर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव जुल्बत निवासी करीब 65 वर्षीय ओमप्रकाश का शव रादौर के एक प्लॉट में खून से लथपथ मिला। देर शाम से घर नहीं लौटने पर परिवार चिंतित था, लेकिन सुबह जब शव मिला तो गांव में सनसनी फैल गई। परिवार ने आरोप लगाया है कि 15 दिन पहले करनाल में ओमप्रकाश के पोते की हत्या हुई थी और ओमप्रकाश लगातार आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे थे। परिजनों का कहना है कि इसी रंजिश के चलते हत्या के आरोपी युवकों ने ओमप्रकाश की भी हत्या कर दी।

राहुल गांधी ने पीएम के मणिपुर दौरे का किया स्वागत, साथ ही वोट चोरी का जिक्र कर निशाना साधा

नई दिल्ली । लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे का स्वागत किया। गुजरात के जूनागढ़ दौरे के दौरान, राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि मणिपुर में लंबे समय से अशांति चल रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मणिपुर में यह मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। यह अच्छी बात है कि वह अब वहां जा रहे हैं। इसके साथ ही वोट चोरी वाले अपने तंज को दोहराते हुए, गांधी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के जनादेश चुराए गए थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि लेकिन देश में मुख्य मुद्दा वोट चोर का है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी जनादेश चुरा लिया गया... हर जगह लोग वोट चोर कह रहे हैं। वहीं, आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर आने में बहुत लंबा समय लग गया... जब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पहुंचेंगे, तो वहां मरहम लगेगा। मणिपुर के लोगों को मरहम की जरूरत है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी औपचारिकता निभा रहे हैं। वह 4 घंटे के लिए जा रहे हैं। उन्हें पहले जाना चाहिए था... मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा कि वह उन्हें समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? ...शायद अगर वह पहले चले जाते, तो शांति जल्दी स्थापित हो जाती। इससे पहले, कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित मणिपुर यात्रा की आलोचना करते हुए इसे राज्य के लोगों का अपमान बताया था। एक्स पर एक पोस्ट में, कांग्रेस सांसद ने यात्रा की तैयारियों से संबंधित एक अखबार की कटिंग साझा की और कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में केवल तीन घंटे ही बिताएँगे। जयराम रमेश ने लिखा, प्रधानमंत्री की 13 सितंबर को प्रस्तावित मणिपुर यात्रा का उनके समर्थक स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह राज्य में लगभग तीन घंटे ही बिताएँगे–हाँ, सिर्फ़ तीन घंटे ही। इतनी जल्दबाज़ी में की गई यात्रा से उन्हें क्या हासिल होने की उम्मीद है?

सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाई। यह समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया, जहाँ राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लाल कुर्ता पहने राधाकृष्णन ने ईश्वर के नाम पर अंग्रेजी में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कैबिनेट मंत्रियों व विपक्षी नेताओं सहित कई अन्य शीर्ष राजनीतिक नेता इस समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद धनखड़ पहली बार सार्वजनिक रूप से इस समारोह में शामिल हुए। इससे पहले 9 सितंबर को, एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उन्हें 452 वोट मिले थे, जबकि विपक्षी उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले थे। तत्कालीन निवर्तमान राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के कारण यह चुनाव आवश्यक हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से गहरी जड़ें रखने वाले तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने 452 वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। उनके प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के संख्यात्मक बल को देखते हुए, राधाकृष्णन की जीत अपेक्षित थी। एनडीए के पास कागजों पर 427 सांसद थे और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 11 सांसदों और कई छोटे दलों का अतिरिक्त समर्थन प्राप्त था, जिससे वह 377 के आधे से भी अधिक बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर गया था। उनके पक्ष में क्रॉस-वोटिंग के संकेत भी मिले थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफे के कारण यह चुनाव आवश्यक हो गया था। अपनी जीत के बाद, राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने नई नियुक्ति होने तक गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कोयंबटूर से दो बार सांसद और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन का दशकों लंबा करियर जनसंघ से शुरू हुआ और फिर भाजपा में शामिल हो गए।

सितंबर 2030 तक होगा कार्यकाल; इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीप धनखड़

सचिन पायलट का बड़ा आरोप, कहा- 'वोट चोरी के प्रमाणों पर जांच नहीं कर रहा निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर 'वोट चोरी' का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग उनकी पार्टी द्वारा चुनावी धांधलियों से जुड़े प्रमाणों के बावजूद कोई जांच नहीं कर रहा है। पायलट ने ईदौर के हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, ''वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है। समूचे देश में हम उन लोगों (भाजपा) के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिन्होंने वोट चोरी की है। इस सिलसिले में निर्वाचन आयोग को प्रमाण भी दिए गए हैं, लेकिन कोई भी जांच नहीं हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं को निरंतर खोखला किया जा रहा है और जनता से उसका वोट का सबसे बड़ा अधिकार जान-बूझकर छीना जा रहा है। पायलट, उज्जैन में कांग्रेस की शुक्रवार को आयोजित किसान न्याय यात्रा में हिस्सा लेने आए थे। उज्जैन, राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर और निर्वाचन क्षेत्र है।

वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर- यात्रा 14 सितंबर से बहाल

जम्मू । खराब मौसम और ट्रैक के जरूरी मरम्मत कार्य के चलते अस्थायी रूप से रोकी गई श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अब 14 सितंबर (रविवार) से दोबारा शुरू की जाएगी। हालांकि, यात्रा की बहाली मौसम अनुकूल रहने पर ही संभव होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि भारी बारिश और ट्रैक की सुरक्षा के लिहाज से यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था। मरम्मत कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है और यदि मौसम सहयोग करता है, तो श्रद्धालु 14 सितंबर से फिर से माता के दर्शन कर सकेंगे। बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मौसम और ट्रैक की स्थिति की जानकारी जरूर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

नेपाल सहित पड़ोसी मुल्कों में राजनीतिक अस्थिरता और भारत पर इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव-एक गहन विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर दक्षिण एशिया आज विश्व राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। नेपाल, जो भारत के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक औरभौगोलिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ है, वर्तमान में एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। सत्ता परिवर्तन, युवा आक्रोश, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन,बाहरी हस्तक्षेप और आर्थिक चुनौतियाँ इससंकट की मुख्य वजहें हैं? भारत के लिए यह स्थिति केवल पड़ोसी की चिंता नहीं है,बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा,सीमाई स्थिरता, आर्थिक व्यापारिक हित और क्षेत्रीय रणनीति से भी गहराई से जुड़ी हुई है।भारत और नेपाल के बीच लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार,पश्चिम बंगाल,उत्तराखंड और सिक्किम से लगती है। यह भौगोलिक निकटता दोनों देशों के संबंधों को विशेष बनाती है। नेपाल के लगभग 80 लाख नागरिक भारत में कामकाज और रोजगार से जुड़े हुए हैं।यह केवल आर्थिक पहलू नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बंधन भी है,क्योंकि लाखों नेपाली परिवार भारत में बसते हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक रिश्ते भी आम हैं।भारत के लिए नेपाल में राजनीतिक स्थिरता इसलिए जरूरी है, क्योंकि यदि वहाँ लगातार सत्ता संकट,विद्रोह या गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है,तो उसका सीधा असर भारत की सीमाओं, सुरक्षा और आंतरिक राजनीति पर पड़ेगा, जो रेखांकित करने वाली बात है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,नेपाल सहित पड़ोसी मुल्कों में राजनीतिक अस्थिरता और भारत पर इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव-एक गहन विश्लेषण। साथियों बात अगर हम नेपाल के युवाओं के स्पष्ट रूप से खुलासा करने की करें तो उन्होंने कहा है कि तोड़फोड़, लूटपाट और हथियार छीनने जैसी घटनाओं में उनका कोई हाथ नहीं है। यह काम कुछ बाहरी तत्वों का है, जिन्होंने आंदोलन में प्रवेश करके उसकी दिशा बदलने की कोशिश की। इस बयान से यह साफ है कि नेपाल का युवा वर्ग केवल पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहता है,न कि अराजकता और हिंसा।भारत के लिए यह संदेश महत्वपूर्ण है। अगर नेपाल में लंबे समय तक चुनाव टाले जाते हैं और स्थिर सरकार नहीं बनती, तो अराजक तत्व और बाहरी शक्तियाँ स्थिति का फायदा उठाकर भारत की सीमाओं में असुरक्षा फैला सकती हैं। साथियों बात अगर हम भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक रिश्ते अति गहरे होने की करें तो,नेपाल के कुल व्यापार का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भारत के साथ होता है। भारत नेपाल को मशीनरी,पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ,खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और औद्योगिक वस्तुएँ भारी मात्रा में निर्यात करता है, जबकि नेपाल से मुख्य रूप से तैलीय बीज, चाय, वन उत्पाद और कुछ सीमित वस्तुएँ ही आयात करता है। इससे भारत का ट्रेड सरप्लस बढ़ता है, लेकिन नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। राजनीतिक संकट से नेपाल की अर्थव्यवस्था और कमजोर होगी, जिससे उसकी खरीद क्षमता घटेगी और भारत के निर्यात पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। साथियों बात अगर हम वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ व डिजिटल डेटा पॉलिसी जैसे मुद्दों पर तनाव चलने की करें तो,ऐसे समय में भारत को अपने निर्यात के लिए नए बाजारों की आवश्यकता है। नेपाल भारत का प्राकृतिक और पारंपरिक बाज़ार रहा है। यदि नेपाल की अर्थव्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता के कारण और कमजोर हो जाती है,तो यह भारत की रणनीति के लिए दोहरी चुनौती होगी।यानें एक ओर अमेरिका से तनाव,और दूसरी ओर नेपाल का संकट,दोनों मिलकर भारत की निर्यात नीति, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। साथियों बात अगर हम इसे चीनी दक्षिण एशिया और वैश्विक संलग्नता के एंगल से देखे तो, नेपाल की अस्थिरता केवल भारत का मामला नहीं है। इस क्षेत्र में चीन भी अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करनेकी कोशिश करता रहा है। चीन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत नेपाल को इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऋण के जाल में फँसाने का प्रयास कर रहा है। अगर नेपाल लंबे समय तक अस्थिर रहता है, तो चीन वहाँ अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश करेगा।भारत के लिए यह सुरक्षा दृष्टि से खतरा है, क्योंकि नेपाल की खुली सीमा भारत की रक्षा नीति के लिए चुनौती बन सकती है।नेपाल की अस्थिरता केवल सीमाई समस्या नहीं पैदा करेगी,बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में अविश्वास और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकती है। यह स्थिति सार्क जैसी क्षेत्रीय संस्थाओं की निष्क्रियता को और गहरा करेगी।साथ ही भारत-बांग्लादेश संबंध, भारत-श्रीलंका संबंध और भारत- भूटान संबंध भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति पर एक प्रकार का डोमिनो प्रभाव पड़ता है। साथियों बात कर हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, लोकतंत्र और न्याय के महत्व की करें तो,10 सितंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के संवैधानिक और राजनीतिक संकट पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस-की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) नेपाल के हालात पर चिंता जताई है,प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान कांस्टीट्यूशन बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है,पड़ोसी देशों की ओर देखिए, नेपाल में हमने देखा, इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा,और बांग्लादेश में भी,पड़ोसी देशों का जिक्र क्यों? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और संविधान को लेकर विवाद जारी हैं,नेपाल में हालात ऐसे बन गए हैं की जनता के गुस्से की वजह से प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा है,चार दिन से देश में आग लगी हुई है, बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले ऐसे ही हालात बने थे और प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। हमें क्यों है गर्व भारत का संविधान दुनियाँ के सबसे बड़ा और सबसे लोकतांत्रिक संविधान में से एक है, इसने न केवल जनता को बराबरी और अधिकार दिए हैं, बल्कि सत्ता में बैठे नेताओं को भी सीमाओं में रहने का सबक सिखाया है, आपातकाल जैसी स्थिति में भी लोकतंत्र ने अपनी राह बनाई और जनता ने संविधान के जरिए ही सत्ता को पलट दिया,न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक फैसलों के जरिए संविधान की आत्मा को मजबूत बनाए रखा है।

सीजेआई की टिप्पणी इसी भरोसे की ओर इशारा करती है कि चाहे कितने भी संकट आएं, भारतीय लोकतंत्र अपने संविधान की वजह से बार-बार मजबूत होकर खड़ा हुआ है। साथियों बात अगर हम वैश्विक स्तरपर सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म और जनआंदोलन की जटिलता की करें तोआधुनिक युग में राजनीति केवल सड़कों और संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। विश्वभर के उदाहरण,फ्रांस में पीली जैकेट आंदोलन, आज 10 सितंबर 2025 को फ्रांसमें जबरदस्त आंदोलन, श्रीलंका में राजपक्षे सरकार का पतन, बांग्लादेश और नेपाल में युवाओं का विद्रोह,यह साबित करते हैं कि सोशल मीडिया जनमत को जिस तरह आकार देता है, वह कभी-कभी स्थिर लोकतंत्रों को भी अस्थिर बना सकता है। एल्गोरिथ्म की समस्या यह है कि यह संतुलित खबरों की जगह अधिक उग्र,सनसनीखेज और विभाजनकारी सामग्री को प्राथमिकता देता है, जिससे समाज में ध्रुवीकरण और असंतोष तेज़ी से फैलता है।भारत को नेपाल के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। क्योंकि अगर सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म के प्रभाव पर गंभीर नियंत्रण और निगरानी नहीं की गई, तो यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के लिए भी खतरा बन सकती है। साथियों बात अगर हम समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की करें तो- (1) नेपाल में शीघ्र और पारदर्शी चुनाव कराना अनिवार्य है।(2) भारत को नेपाल के साथ कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएँ मजबूत हों।(3) सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म और बाहरी तत्वों पर सख्त निगरानी जरूरी है।(4) नेपाल की आर्थिक कमजोरी दूर करने के लिए भारत को संतुलित व्यापार नीति अपनानी होगी।(5)क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत, नेपाल और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच बहुपक्षीय संवाद होना चाहिए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि नेपाल की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता केवल एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह भारत और पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है।

सम्पादकीय...

सेमीकंडक्टर की दौड़ में भारत

पिछले सप्ताह सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन और पीएम नरेंद्र मोदी के इस इवेंट में शिरकत करने के बाद सेमीकंडक्टर चिप को लेकर हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी का कहना है कि सरकार 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन' और उसको तैयार करने से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अगले फेज पर काम कर रही है। सेमीकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, -हम भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण पर काम कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब भारत में बनी सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। सरकार नई डीएलआई (डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव) योजना को आकार देने जा रही है। मोबाइल, कंप्यूटर, राउटर, कार, सैटेलाइट जैसे एडवांस्ड डिजिटल डिवाइस का 'दिमाग' सेमीकंडक्टर चिप है। जी हां, इन सब आधुनिक डिवाइसेज की ताकत इस एक छोटी-सी चिप में बसती है। आज हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, उसकी धड़कन सेमीकंडक्टर चिप है। मोबाइल फोन से लेकर इंटरनेट, कारों से लेकर मिसाइल और अंतरिक्ष यानों तक हर एडवांस तकनीक का दिमाग यही सेमीकंडक्टर चिप है। दुनिया भर के देशों में सेमीकंडक्टर चिप के बाजार पर कब्जा करने की होड़ मची है। 'विक्रम' 32 बिट प्रोसेसर और चार सेमीकंडक्टर टेस्ट चिप बनाकर भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटाप, कार, इलेक्ट्रिक वाहन, टीवी, वाशिंग मशीन से लेकर इंटरनेट, क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक में होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार करीब 600 अरब डालर (करीब 52 लाख करोड़) का है। 2030 तक इस बाजार के एक ट्रिलियन डालर यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। फिलहाल दुनिया में कहीं भी सेमीकंडक्टर चिप बन रही है, उसमें भारतीय इंजीनियरों का कुछ न कुछ योगदान जरूर होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ग्लोबल डिजाइन सेंटर में बड़ी तादात में आपको भारतीय इंजीनियर मिलेंगे। अभी तक हम ग्लोबल कंपनियों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब उत्पादन और डिजाइन हमारे होंगे। भारत में इस वक्त सेमीकंडक्टर का बाजार करीब दो लाख करोड़ का है, जो 2030 तक बढ़कर करीब 5 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। फिलहाल ताइवान दुनिया की करीब 60 फीसद चिप बनाता है। डिजाइन और इनोवेशन के मामले में अमेरिका का दबदबा है और चीन तेजी से बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए कई योजनाएं बनाई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चिप निर्माण के लिए 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। इसमें से 65,000 करोड़ रुपये चिप निर्माण के लिए और 10,000 करोड़ रुपये मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किए गए हैं। डीप टेक भारत 2025 यह पहल आईआईटी कानपुर में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और बायोमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली- इस प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को केंद्र और राज्य सरकारों से अनुमतियां एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज होती है। वर्तमान में, भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और निर्माण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं मसलन नोएडा और बेंगलुरु में अत्याधुनिक डिजाइन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां बिलियनों ट्रांजिस्टर्स वाले चिप्स पर काम हो रहा है। 28 स्टार्टअप्स चिप डिजाइनिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं, जो नवाचार और विकास में योगदान दे रहे हैं। सरकार ने 10 लाख से अधिक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिससे मानव संसाधन की क्षमता में वृद्धि हुई है। भारत के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं. भारत, ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ मिलकर वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन सकता है। नौकरियों का सृजन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश से लाखों नई नौकरियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो रोजगार के अवसर प्रदान करेंगी। स्थानीय उत्पादन से आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर देश न केवल सेमीकंडक्टर डिजाइन और पैकेजिंग में बल्कि फैब निर्माण एवं हाई-एंड विकल विकास में वैश्विक मंच पर उभरने को तत्पर है। बहरहाल कई बातें ऐसी भी हैं कि जिन्हें सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, सहयोग की प्रकृति रणनीतिक होनी चाहिए। भारत संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का स्थानीयकरण करने की नहीं सोच सकता। इस मिशन को उन विशिष्ट क्षेत्रों पर प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां विदेशी निर्भरता, खासतौर पर चीन पर निर्भरता एक रणनीतिक जोखिम के रूप में देखी जा सकती है। गौर करने वाली बात है कि अभी दुनिया में कुछ देशों और कंपनियों में ही चिप मैन्युफेक्चरिंग होती है। सप्लाई में रुकावट, भूराजनीतिक तनाव और नई तकनीक की मांग ने विविधता की जरूरत को बढ़ा दिया है। अब भारत का इरादा इस सेक्टर में अपने बड़े बाजार, इंजीनियरिंग टैलेंट, नीतिगत सपोर्ट और कॉस्ट-कॉम्पटीशन की ताकत पर अपनी जगह बनाना है। और भारत केवल बाजार नहीं बल्कि को-डेवलपमेंट और को-इनोवेशन पार्टनर बनना चाहता है।भारत सेमीकंडक्टर नवाचार और निर्माण के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। सरकार की नीतियां, निवेशकों का विश्वास और युवा शक्ति इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रही है। यदि यह गति बनी रहती है, तो भारत आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।

दबंग दबक गया ?

दबाव बनाने वाला अब पीछे हटता दिखाई दे रहा है, कम से कम ऊपर-ऊपर तो यही तस्वीर है। अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं। करीब आठ माह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतकर पूरी दुनिया को झकझोर देने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज भी अपने अप्रत्याशित और सनकी तेवरों, साथ ही चौंकाने वाली नीतिगत घोषणाओं से हलचल मचाए हुए हैं। कहना गलत न होगा कि उन्होंने वैश्विक व्यवस्था को इस हद तक हिला दिया है, जिसकी कल्पना भी लोगों ने की होगी। सूची में सबसे ऊपर है अवैध प्रवासियों पर नकेल कसना और 'न्याय संगतता' के नाम पर आयातित वस्तुओं पर उतना ही शुल्क लगाना जितना अन्य देश अमेरिकी उत्पादों पर लगाते हैं। इसी बहाने ट्रंप ने एक ऐसे व्यापार युद्ध का शंखनाद कर दिया है, जिसके असर दूरगामी और गहरे हैं। यह कदम न केवल दशकों पुरानी व्यापार नीतियों को उलट चुका है, बल्कि बहुराष्ट्रीय व्यवसायों के लिए अराजकता और अस्थिरता भी ले आया है। ट्रंप के नज़रिए से देखें तो यह महज़ एक चुनावी वादे की पूर्ति है। याद कीजिए उनका शपथ ग्रहण भाषण, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि 'विदेशी देशों पर शुल्क और कर लगाकर हम अपने नागरिकों को समृद्ध करेंगे।' लेकिन अब यही वादा भारी बोझ का रूप ले चुका हैऔर यह बोझ, हल्के शब्दों में भी कहें तो, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। कट टू 2025 – ट्रंप के नए हमले दो मुद्दों पर- ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान युद्धविराम और भारत को 'टैरिफ किंग' तथा 'बड़ा गलत इस्तेमाल करने वाला' करार देना। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच भयंकर झड़पें हुईं और अंततः युद्धविराम की स्थिति बनी। लेकिन इससे पहले कि भारत या पाकिस्तान आधिकारिक घोषणा कर पाते, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिख दिया 'भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमति जताई है।' कहना गलत न होगा कि ट्रंप ने जल्दबाज़ी दिखाकर भारतीय सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी में डाल दिया और हमारे सशस्त्र बलों के उस दावे को भी कमजोर कर दिया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सरकार ने ट्रंप के दावों का खंडन तो किया, लेकिन बेहद अप्रत्यक्ष और कमजोर ढंग से। बार-बार यही कहा गया कि युद्धविराम केवल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। मगर न एक बार ट्रंप का नाम लिया गया, न अमेरिका का ज़िक्र करके उनके दावे को सिरे से खारिज किया गया। यहां तक कि जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को चुनौती दी कि वह साफ़ कहे 'ट्रंप झूठ बोल रहे हैं' तब भी सरकार चुप्पी साधे रही। निष्कर्ष साफ़ था मोदी ट्रंप का सीधा सामना करने से बच रहे थे। जहां तक टैरिफ़ का सवाल है, ट्रंप राष्ट्रपति बनने के समय से ही भारत के ऊंचे आयात शुल्क की आलोचना करते आ रहे थे। रिकॉर्ड के लिए बता दें, टैरिफ़ यानी किसी देश से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 'अब मैं ज़िम्मेदारी संभाल रहा हूं और आप ऐसा नहीं कर सकते' स्पष्ट था कि यह धमकी महज़ बयानबाज़ी नहीं थी।

पिछले महीने ट्रंप ने भारत से आयात पर शुल्क दोगुना कर दिया, इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। इसमें रूस से तेल खरीद पर लगाया गया 25 प्रतिशत का दंडात्मक शुल्क भी शामिल था जो अमेरिका ने किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक है। ट्रंप प्रशासन का संकेत साफ़ था 'रूस से तेल और हथियार खरीदने की सज़ा।' लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग रास्ता चुना और मजबूती से कदम उठाया। उन्होंने ट्रंप और दुनिया को यह संदेश दिया कि राष्ट्रीय हित के मामले में भारत किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। और यही हुआ। नतीजा यह रहा कि मोदी के इस कदम ने न केवल ट्रंप बल्कि पूरे अमेरिकी तंत्र को असहज कर दिया। संकेत साफ़ है भारत अब अमेरिका-केंद्रित नीति से आगे बढ़कर नए वैश्विक समीकरण गढ़ रहा है। हालिया शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की तियानजिन, चीन बैठक में रूस और चीन के साथ भारत की कूटनीतिक नज़दीकियां इसी बदलाव की बानगी हैः शुरुआत हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाथों में हाथ डाले बैठक कक्ष में दाखिल हुए, जहां पहले से ही कई विश्व नेता मौजूद थे। दोनों सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर बढ़े, उनसे हाथ मिलाया और तीनों ने मिलकर एक नज़दीकी घेरा बना लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने शिखर सम्मेलन के इतर होने वाली एक बैठक में साथ गाड़ी साझा की। आधिकारिक बातचीत शुरू होने से पहले दोनों ने पुतिन की लिमोज़ीन में लगभग 50 मिनट तक गहन चर्चा की। शी और पुतिन की आत्मीयता का संदेश साफ़ था अमेरिका की चुनौती के समानांतर एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था खड़ी करने का इरादा। मोदी का मकसद यह दिखाना था कि भारत के पास भी मजबूत दोस्त हैं, यहां तक कि चीन भी, भले ही सीमा विवाद अब तक सुलझा न हो- अगर ट्रंप प्रशासन टैरिफ़ लगाकर भारत को दूर धकेलना जारी रखता है। तियानजिन की बैठक में यह तस्वीर पूरी तरह सामने आई। विश्लेषकों ने कहा-इस शिखर सम्मेलन की असली ताक़त प्रतीकों में है, और व्हाइट हाउस को समझना चाहिए कि उसकी नीतियां अन्य देशों को अपने हित साधने के लिए वैकल्पिक साझेदार तलाशने पर मजबूर कर रही हैं। उनका मानना था कि मोदी, पुतिन और शी का हाथ में हाथ डालना और मुस्कुराना उस 'त्रिमूर्ति' का जीवंत प्रतीक है, जिसे मास्को लंबे समय से पुनर्जीवित करना चाहता है। संदेश बिल्कुल साफ़ था- पश्चिमी गुट से बाहर की तीन बड़ी ताक़तें, हंसते-मुस्कुराते, दोस्ताना अंदाज़ में दुनिया को यह दिखा रही थीं कि वे एकजुट हैं। यह केवल प्रतीकात्मकता थी, लेकिन बेहद सशक्त। ट्रंप और अमेरिका को इसका सीधा संदेश गया- 'अब और दबाव मत डालो।' यही था प्रधानमंत्री मोदी का इशारा ट्रंप की धौंस भरी राजनीति की ओर। ट्रंप ने अंततः यू-टर्न ले ही लिया। उन्होंने कहा-अमेरिका ने शायद भारत और रूस को चीन के गहरे अंधेरे खेमे में खो दिया है। इतना ही नहीं, आगे बढ़कर उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि 'मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। यह कदम देर से आया, और शायद थोड़ा कमज़ोर भी। साफ़ है कि ट्रंप घबराए हुए हैं और होना भी चाहिए। उन्हें लगा था कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी को अपनी उंगली पर नचाकर दबाव बनाया जा सकता है। मगर वह भूल गए कि मोदी कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं। जब बात राष्ट्रीय हित की आती है तो प्रधानमंत्री मोदी समझौते की बजाय सीधा पलटवार करना जानते हैं। लोग चाहे यह मानते रहे हों कि मोदी ट्रंप के दबाव में हैं और उनके इशारों पर चलते हैं, लेकिन मोदी ने यह धारणा पूरी तरह तोड़ दी। ट्रंप ने जब टैरिफ़ का वार किया तो मोदी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने ट्रंप की 'ब्लफ़' को उजागर कर यह दिखा दिया कि भारत न तो अमेरिका पर निर्भर है और न ही ट्रंप की मनमानी के आगे झुकने को तैयार। भारत अपने दम पर खड़ा रह सकता है और ऐसे विकल्प तलाश सकता है जो अमेरिका को उससे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं जितनी अमेरिका भारत को पहुंचा सकता है। यह सच है कि भारत-चीन-रूस की त्रिमूर्ति में मतभेद और दरारें भी मौजूद हैं। मगर फिलहाल, कम से कम भारत के लिए, इस हाथ-में-हाथ डालने वाली तस्वीर ने मकसद पूरा कर दिया है। इससे भी अहम संदेश यह गया है कि भारत अब अमेरिका के साथ या उसके बिना, हर संभव विकल्प तलाशेगा। इसलिए, ट्रंप को समझना होगा कि भारत को खोना उनके लिए खुद एक भारी जोखिम होगा। अगर वह रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं तो अब सारी शर्तें केवल वॉशिंगटन से तय नहीं होंगी। प्रधानमंत्री मोदी यह कभी नहीं होने देंगे।

पटरी पर लौटता नेपाल

भारत और नेपाल में दो सहोदर भ्राताओं जैसे रिश्ते रहे हैं जिनमें रोटी और बेटी तक का सम्बन्ध रहा है। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद इन रिश्तों में और प्रगाढ़ता आयी और दुनिया के एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल के साथ भारत ने अपने अटूट ऐतिहासिक सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत किया। दोनों देशों के बीच सैनिक सम्बन्ध भी इस प्रकार के स्थापित हुए कि नेपाल की सुरक्षा की गारंटी तक भारत ने ली और नेपाली जनता के लिए भारत के द्वार हर तरफ से खोले तथा इसके विकास व प्रगति में अपना पूरा योगदान दिया। जाहिर है कि इनमें आर्थिक रिश्ते भी बहुत महत्व रखते थे, अतः भारत ने नेपाल के समग्र आर्थिक विकास में अपना पूरा योगदान दिया। परन्तु शुरू में राजशाही में चलने वाले नेपाल में 2008 में जब राजशाही का अन्त हुआ और यहां की जनता के उग्र आन्दोलन के स्वरूप नेपाल एक गणतान्त्रिक व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हुआ, तो इसका संविधान बनाने में भारत ने पूर्ण सहयोग किया मगर तब तक नेपाल पर चीन का आंशिक प्रभाव भी प्रभावी होने लगा था।

अतः गणतान्त्रिक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टियों का भी प्रभाव बढ़ा। गणतान्त्रिक नेपाल में कम्युनिस्टों को फलने-फूलने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ मगर ये पार्टियां भारत के साथ इसके अन्तः सम्बन्धों को नहीं तोड़ पाईं। वर्तमान में नेपाल में जो जन आन्दोलन खड़ा हुआ उसे पूरी तरह जनता का स्फूर्त आन्दोलन कहना उचित नहीं होगा क्योंकि इस आन्दोलन के तहत चुन-चुन कर लोकतान्त्रिक संस्थानों पर हमला किया गया और 2015 से लागू नेपाल के संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं। इस आन्दोलन में कहीं न कहीं चीन विरोधी शक्तियों की भूमिका भी नजर आती है। क्योंकि नेपाल से पहले बंगलादेश व श्रीलंका में भी हमें यही देखने को मिला। मगर इससे चीन को भी वैधानिकता नहीं मिल जाती है क्योंकि इसने इन तीनों ही देशों में अपना आर्थिक विस्तार करके भ्रष्टाचार को ही कहीं न कहीं बढ़ावा दिया। बंगलादेश में तो वहां की भारत की मित्र शेख हसीना सरकार को उखाड़ा गया और यही हाल श्रीलंका में भी हुआ मगर नेपाल में तो चीन ने अपनी शक्ति का विस्तार राजनीतिक स्तर पर भी बहुत तेजी के साथ किया था। वरना एक जमाने में यहां की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस ही हुआ करती थी जो राजशाही के दौरान यहां की पंचायत राज प्रणाली की कर्णधार मानी जाती थी। वर्तमान में पिछले कुछ दिनों में नेपाल में जो कुछ भी हुआ है उसे केवल भीषण अराजकता ही कहा जा सकता है जिसमें जनता ने अपने ही बनाये राष्ट्रीय संस्थानों को तहस-नहस किया। अतः भारत के बारे में भी ऐसा ही कुछ सोचने वाले लोग न केवल गलती पर हैं बल्कि राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं क्योंकि भारत में लोकतन्त्र की जड़ें बहुत गहरी हैं जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जमाकर गये हैं। महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान सबसे ज्यादा जोर व्यक्ति की गरिमा व उसके आत्मसम्मान पर दिया जिससे स्वतन्त्र भारत का वह स्वयं शासक एक वोट के अधिकार के माध्यम से बन सके। इसके साथ ही बापू ने सर्वाधिक जोर अहिंसा पर दिया जिससे किसी भी सूरत में स्वतन्त्र भारत में किसी भी स्तर पर अराजकता पैदा न हो सके। गांधी के देश में यह फार्मूला समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है अतः भारत में अराजकता की बात करने वाले लोग भारतीय संविधान की उस ताकत की अनदेखी करते हैं जिसमें प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिये गये हैं। गांधी के आन्दोलन का प्रभाव नेपाल पर भी न पड़ा हो ऐसा नहीं है। वस्तुतः नेपाली कांग्रेस गांधी के आन्दोलन की ही उपज थी जो शान्तिपूर्ण तरीकों से राजशाही के तहत जनता के अधिकारों के लिए लड़ी। वर्तमान में लगातार कई दिनों तक हिंसा करने के बाद नेपाल को क्या मिला? विध्वंस कभी भी किसी राष्ट्र का ध्येय नहीं हो सकता। विध्वंस से केवल नकारात्मकता का ही सृजन होता है जो कि व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है अतः कुछ दिनों के विध्वंस के बाद नेपाली सेना ने स्थिति को अपने नियन्त्रण में लिया और सामान्य हालात बनाने के प्रयास किये। सवाल पूछा जा सकता है कि जब लगातार दो दिन तक नेपाल की सड़कों पर तांडव हो रहा था तो सेना क्यों चुप थी? इसका उत्तर है कि तब तक नेपाल में लोगों की चुनी हुई के.पी. शर्मा ओली की सरकार सत्ता पर काबिज थी और शासन पर उसी का नियन्त्रण था। सेना ने तभी कमान संभाली जब यह सरकार बेअसर हो गई और प्रशासन पर इसकी पकड़ समाप्त हो गई। इसका निष्कर्ष यह भी निकाला जा सकता है कि नेपाली सेना भी लोकतन्त्र का सम्मान करती है और वह समस्या का हल इसी दायरे में ढूंढना चाहती है। क्योंकि नेपाल के सेना प्रमुख ने स्वयं सत्ता संभालने की बात नहीं कही है बल्कि उन्होंने यहां के राष्ट्रपति को अपने संरक्षण में रखा हुआ है। नेपाल और बंगलादेश की अराजकता में यही मूलभूत अन्तर है। जैसी खबरें मिल रही हैं उनके अनुसार इस देश की सत्ता प्रमुख देश के सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश रहीं श्रीमती सुशीला कार्की नई प्रधानमन्त्री हो सकती हैं क्योंकि उनके नाम पर आन्दोलनकारियों में भी सहमति बताई जाती है। हालांकि कुछ और नाम भी हवा में तैरने शुरू हो गये हैं। परन्तु नेपाल की स्थिति को देखते हुए श्रीमती कार्की सर्वश्रेष्ठ चुनाव लगती हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो इसकी मंशा नेपाल की स्थिरता के लिए ही हो सकती है क्योंकि एक स्थिर व विकसित नेपाल भारत के हित में है। भारत किसी दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है मगर वह इस बात का हिमायती रहता है कि किसी भी देश में सरकार वहां की जनता की इच्छा के अनुरूप ही बननी चाहिए।

सादगी, ताक़त और आधुनिकता का संगम है मोदी के मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संपत्ति का विवरण जारी किया गया है। पहली नज़र में यह सूची केवल आभूषण, ज़मीन, गाड़ियों और निवेशों का ब्योरा लगती है, लेकिन गहराई से देखने पर यह भारतीय राजनीति की मानसिकता, सामाजिक प्रतीकवाद और सत्ता की शैली का आईना बन जाती है। सबसे पहले ध्यान आकर्षित करता है जयंत चौधरी का क्रिप्टो निवेश। वह अकेले मंत्री हैं जिन्होंने डिजिटल संपत्ति घोषित की है। उन्होंने करीब 43 लाख रुपये के बिटकॉइन जैसे निवेश किये हैं। यह उस समय में खास महत्व रखता है जब भारत में क्रिप्टो अब भी कानूनी अनिश्चितता में है और RBI लगातार इससे जुड़े जोखिमों की चेतावनी देता रहा है। यह खुलासा दिखाता है कि नए दौर का नेतृत्व जोखिम लेने और नए वित्तीय प्रयोग करने से पीछे नहीं हट रहा। इसके विपरीत, कई मंत्रियों ने पुराने वाहन अपनी संपत्ति में शामिल किए हैं। नितिन गडकरी की 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार, विरेंद्र कुमार का 37 साल पुराना स्कूटर और रवनीत बिट्टू की 1997 मॉडल की मारुति, ये सब केवल धातु के ढांचे नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश हैं। जनता को यह बताना कि नेता अब भी 'साधारण' हैं, विलासिता से दूर हैं और परंपरा को संजोए हुए हैं। लेकिन इस सादगी के बीच एक और पैटर्न साफ़ झलकता है- हथियारों की मौजूदगी। रिवॉल्वर, पिस्तौल और राइफल घोषित करने वाले मंत्री कम नहीं हैं। यह उस सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है जहाँ ताक़त का प्रदर्शन और व्यक्तिगत सुरक्षा सत्ता के साथ कदमताल करती है। सबसे बड़ा हिस्सा, अपेक्षा के अनुसार सोने और आभूषणों का है। राव इंद्रजीत सिंह के पास 1.2 करोड़ रुपये से अधिक का सोना और हीरे हैं, नितिन गडकरी व एल. मुरुगन के पास भी लाखों के आभूषण हैं। देखा जाये तो भारतीय समाज में आभूषण सदियों से आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों का प्रतीक रहे हैं, मंत्रियों की संपत्ति भी इस परंपरा को दोहराती है। मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास 27 लाख से अधिक के आभूषण, म्यूचुअल फंड में 19 लाख से ज्यादा और एक दोपहिया वाहन है। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पास भी रिवॉल्वर, राइफल, ट्रैक्टर और लगभग 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर के पास डबल बैरल गन और रिवॉल्वर तथा 67 लाख से ज्यादा के सोने के आभूषण हैं। देखा जाये तो इन संपत्तियों का सार्वजनिक खुलासा लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी है। यह जनता को भरोसा दिलाने का प्रयास भी है कि नेता अपनी आर्थिक स्थिति छिपा नहीं रहे। लेकिन इन घोषणाओं का एक दूसरा पहलू भी है कि संपत्ति अब केवल निजी स्वामित्व नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गई है। बहरहाल, मोदी सरकार के मंत्रियों की घोषित संपत्तियाँ केवल रकम और वस्तुओं का हिसाब नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की बदलती शैली का दस्तावेज़ हैं। यह दस्तावेज़ बताता है कि सत्ता में बैठे लोग जनता को साधारण, शक्तिशाली, पारंपरिक और आधुनिक, सभी रूपों में संदेश देना चाहते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कपल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सायं पश्चिमी क्षेत्र, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/...)

अटेवा की बैठक में सदस्यता पर दिया गया ज़ोर

फतेहपुर।

आज अटेवा पेंशन बचाओ मंच फतेहपुर की एक बैठक अंबेडकर पार्क कचहरी फतेहपुर में जिला अध्यक्ष निधान सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की बैठक में प्रदेश की कार्यकारिणी से प्राप्त दिशा निर्देशों को साझा किया गया। बैठक में वर्तमान सत्र की गतिमान सदस्यता की समीक्षा की गई तथा सभी साथियों को निर्देशित किया गया कि अल्प से समय में बचे हुए साथियों को सदस्य बनाया जाए। देवेंद्र पांडेय जिला कोषाध्यक्ष ने कहा कि सभी ब्लॉकों के साथियों को एमएलसी वोटर के फॉर्म दिए गए थे सभी साथियों ने फॉर्म भर लिए अथवा नहीं और अधिक साथी एमएलसी फॉर्म भरें और अपने परिवार के सदस्यों व मित्रों को भी स्नातक एमएलसी के फॉर्म भरवायें तथा जल्द ही जिम्मेदार साथियों के पास जमा करें। अरविंद विश्वकर्मा जिला सोशल मीडिया प्रभारी ने कहा कि अटेवा संगठन

पुरानी पेंशन बहाली हेतु लगातार आंदोलन कर रहा है आगामी 25 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले विशाल धरना प्रदर्शन के लिए अधिक से अधिक साथी 26 सितंबर से टिकट बुक करवा लें, यदि टिकट में कोई समस्या होती है तो जिला कार्यकारिणी से संपर्क करें। जिला अध्यक्ष निधान सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में हमारे शिक्षक साथियों की नौकरी में टेट का एक प्रकरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया है इस समस्या के समाधान के लिए भी हमारा संगठन प्रयत्नशील है। इसी क्रम में पहले चरण में संगठन ने प्रथम चरण में सांसदों/विधायकों को ज्ञापन देना है इस क्रम में सभी साथियों को अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन देना है। अनिल कुमार सविता संरक्षक अटेवा बहुआ ने कहा कि सभी के लिए ज्ञापन देने का कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया जाए। जिसमें जिला महामंत्री महेंद्र मौर्य ने बताया कि विजयीपुर धाता की टीम खागा विधायक कृष्णा पासवान को, ऐरायां व हथगाम की टीम हुसैनगंज विधायक उषा मौर्य को बहुआ व असोथर टीम अयाह शाह विधायक विकास गुप्ता को, तेलियानी, भिटौरा व हसवा टीम सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी जी को, मलवा व खजुहा टीम बिंदकी विधायक जयकुमार सिंह जैकी को, देवमई व अमौली टीम जहानाबाद विधायक राजेंद्र पटेल को व जिला कार्यकारिणी फतेहपुर सांसद नरेश उत्तम को सुप्रीम कोर्ट के टेट वाले निर्णय के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपेगे।जिसमें अधिक से अधिक साथियों को प्रतिभाग करना है। आज की बैठक में रामभुवन चौधरी, महेंद्र सिंह, वीर महेंद्र, अनिल कुमार सविता, कीर्ति कुमार पाल, धीरेंद्र सिंह, श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव, हेमचंद चौधरी, अजय कुमार, उदित कुमार सचान,अरविंद विश्वकर्मा, अजय सविता, आशीष कुमार सोनी, रमेश कुमार सिंधिया सहित अन्य पदाधिकारी लोग बैठक में उपस्थित रहे।

15 को देशभर में प्रदर्शन करेगा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

मुरादाबाद।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (एबीआरएसएम) ने टीईटी अनिवार्यता के उ'चतम न्यायालय के आदेश से देश के 20 लाख से भी अधिक शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा पर आए संकट के समाधान हेतु प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील की है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा 15 सितंबर को पूरे देश भर के जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर टीईटी समस्या समाधान का आग्रह किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संजय मेधावी एवं प्रदेश महामंत्री जोगेंद्र पाल सिंह ने संयुक्त बयान में कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से टीईटी समस्या के समाधान हेतु 15 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर इस जवलंत समस्या के समाधान की मांग करेगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 15सितंबर को ज्ञापन के माध्यम से 01 सितम्बर 2025 को उ'चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस निर्णय के अनुसार कक्षा आठ तक पढ़ाने वाले सभी सेवारत शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, चाहे उनकी नियुक्ति की तिथि कुछ भी रही हो। यह स्थिति देशभर के लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और आजीविका को संकट में डाल सकती है।

वन्य जीव सक्रियता क्षेत्रों में के लिए गठित किये गये 11 गश्ती दल

वन्य जीव की खोज में ली जा रही है ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों की मदद

बहराइच ।

डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि बहराइच वन प्रभाग, बहराइच के कैसरगंज रेंज के तहसील कैसरगंज अन्तर्गत 09 सितम्बर 2025 को ग्राम-परागपुरवा, पो. मझारा तौकत्ती, थाना व तहसील कैसरगंज में अज्ञात वन्य जीव द्वारा 11/12 सितम्बर 2025 की रात्रि लगभग 03:00 बजे ग्राम-भौरी, मजरा बहोरवा, पो. मंझारा तौकती, थाना बौण्डी तहसील महसी में अज्ञात वन्य जीव द्वारा किये गये हमले के दृष्टिगत प्रभाग स्तर से 07 एवं वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा स्तर से 04 गश्ती टीमों का गठन किया गया है जो दिवस/रात्रि वन्य जीव सक्रियता क्षेत्रों में गश्त की कार्यवाही कर रही है।

डीएफओ श्री यादव ने बताया कि वन्य जीव सक्रियता वाले क्षेत्र में 03 थर्मल ड्रोन कैमरों को चलाकर तथा संवेदनशील स्थानों पर कैमरा ट्रैप्स को स्थापित कर वन्य जीव को खोजने की कार्यवाही की जा रही है। वन्य जीव के हमले से प्रभावित ग्रामों में सोलर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। ताकि वन्य जीव की पहचान सुनिश्चित करते हुए उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। गश्ती टीमों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पैदल चलकर सक्रिय वन्य जीव को चिन्हित किये जाने एवं पगमार्क खोजने की कार्यवाही की जा रही है। डीएफओ ने बताया कि जनजागरूता टीमों द्वारा स्थानीय ग्रामीणजनों को हिंसक वन्य जीवों से बचाव हेतु लगातार जागरूक किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र के ग्रामवासियों को रात्रि में अपने घरों के अन्दर दरवाजा बन्द करके स्वयं एवं बच्चों को सुरक्षित सुलाने हेतु आग्रह किया जा रहा है। गश्ती टीमें द्वारा प्रभावित ग्राम के बाहरी क्षेत्रों में पटाखों को दगाकर वन्य जीव को रोकने की कार्यवाहियों की जा रही है। उन्होंने बताया कि वन, पुलिस एवं जिला प्रशासन के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए हिंसक जीव के हमले से प्रभावित क्षेत्र में दिवारात्रि गश्त की जा रही है जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं होने पायी है।

इज़रायल का क़तर पर हमला, इमाम खुमैनी की आधी सदी पुरानी चेतावनियों की गूंज : आयतुल्लाह सैयद हसन खुमैनी

लखनऊ। ईरान के एक प्रमुख धर्मगुरु और इमाम खुमैनी के पोते आयतुल्लाह सैयद हसन खुमैनी ने क़तर पर इज़रायल के हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम अमेरिका समर्थित इज़रायली नीतियों की निरंतरता है, जिसका मकसद पूरे मध्य-पूर्व में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है। सैयद हसन खुमैनी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आज की असल समस्या ईरान का परमाणु या मिसाइल कार्यक्रम नहीं, बल्कि क्षेत्र में इज़रायल का बढ़ता हुआ नियंत्रण और शक्ति है। यह शक्ति सभी राजनीतिक, सैन्य, मानवीय और नैतिक सीमाओं को पार करने के बराबर है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रों के जीवन और सम्मान की रक्षा करना, साथ ही सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करना एक मानवीय जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, क़तर पर हमला पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और यह उस नीति को दिखाता है जिसके बारे में इमाम खुमैनी ने आधी सदी पहले ही चेतावनी दी थी। सैयद हसन खुमैनी ने आगाह किया कि लेबनान, ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों में भी ऐसे हमलों की संभावना है। उन्होंने कहा कि इन साझा खतरों का एकमात्र प्रभावी जवाब इस्लामिक देशों के बीच सच्ची एकजुटता है। उन्होंने यह भी कहा, आपसी मतभेद दुश्मन के लिए सबसे बड़ा अवसर होते हैं, और इन खतरों को केवल एकता के माध्यम से ही रोका जा सकता है। इसी मौके पर, इमाम खुमैनी संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मामलों के विभाग ने 39वें अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक एकता सम्मेलन में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें इमाम खुमैनी के बहुभाषी लेख और कार्य दिखाए गए। इसका उद्देश्य दुनिया भर के बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एक पुल स्थापित करना था।

स्कूल बैंड प्रतियोगिता में जीजी हिंदू इंटर कॉलेज ने मारी बाज़ी

मुरादाबाद। माध्यमिक विद्यालयों की जनपद स्तरीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला परियोजना अधिकारी मुरादाबाद के निर्देशानुसार जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद में किया गया जिसका उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. कुलदीप बरनवाल ने प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर किया तथा अ'छे प्रदर्शन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी इ प्रतियोगिता में मेजबान विद्यालय जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद तथा एसएस इंटर कॉलेज मुरादाबाद की बैंड टीम ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों ने क्रिक मार्च, स्लो मार्च तथा देशभक्ति गीतों की धुन पर शानदार प्रस्तुतियां दी जिसे उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्र-छात्राओं ने तालियां बजाकर खूब सराहा। निर्णायक का दायित्व विमलेंद्र कुमार शर्मा, वीर सिंह तथा वंश बहादुर ने निभाया। उप प्रधानाचार्य वीरेश कुमार गौतम जी ने कहा कि छात्र छात्राओं के अंदर देश प्रेम व एकता की भावना को विकसित करने के लिए विद्यालयों में स्कूल बैंड का होना जरूरी है। प्रतियोगिता में सुंदर व आकर्षक प्रस्तुति देते हुए जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि एसएस इंटर कॉलेज मुरादाबाद उपविजेता रहा। जिला नोडल अधिकारी/ प्रवक्ता जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद बंश बहादुर ने बताया कि रा'य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा (माध्यमिक) 18 पार्क रोड लखनऊ तथा जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला परियोजना अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे के निर्देशानुसार यह जनपद स्तरीय स्कूल बैंड की प्रतियोगिता 2025 आयोजित की गई है। इस अवसर पर ऊदल सिंह, अरविंद मोहन पांडे, डॉ0 सुनीत गिरी, डॉ सुधीर कुमार आदि शिक्षक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

टीएमयू में एडवांस डेंटल इम्प्लांट क्लिनिक का शुभारंभ

मुरादाबाद।

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में एडवांस डेंटल इम्प्लांट क्लिनिक का यूनिवर्सिटी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन ने फीता खोलकर उद्घाटन किया। यह एडवांस डेंटल इम्प्लांट क्लिनिक अतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं, डेंटल चेयर्स और नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित है। उद्घाटन समारोह में इंडी श्री जैन बोले, यह क्लिनिक रोगियों, शोधकर्ताओं और डेंटल छात्रों के लिए के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिससे डेंटल इम्प्लांट के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और गहन प्रशिक्षण

उपलब्ध हो सकेगा। कार्यक्रम में डेंटल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. प्रदीप तांगड़े, उप-प्राचार्य डॉ. अंकिता जैन, पेरियोडोंटिक्स विभाग के एचओडी प्रो. शलभ मेहरोत्रा आदि की गरिमामयी उपस्थिति रही। डेंटल कॉलेज की उप-प्राचार्य डॉ. अंकिता जैन बताती हैं, एडवांस डेंटल इम्प्लांट क्लिनिक में ब्राजील में निर्मित ये एस-500 डेंटल चेयर्स तमाम फीचर्स से लैस हैं। परम्परागत चेयर्स की तुलना में ये चेयर्स पेशेंट के लिए 'यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हैं। इन चेयर्स के फीचर्स दिव्यांग पेशेंट्स और ब'चों के लिए वरदान साबित होंगे। इन चेयर्स पर राइट एंड लेफ्ट हैंडेड डॉक्टर्स भी आसानी से कार्य सकेंगे। इम्प्लांट करते समय पेशेंट को यदि कोई असुविधा होती है तो इन चेयर्स में इमरजेंसी बटन का भी प्रावधान है। ये चेयर्स सिंक्रोनाइज सुविधा युक्त हैं मतलब इन चेयर्स को साथ-साथ अप-डाउन और राइट-लेफ्ट मूमेंट किया जा सकता है। चेयर्स ऑटोमेटिक कीटाणुनाशक प्रक्रिया से भी लैस हैं।

राजस्व और चकबंदी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित

मुरादाबाद।

कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह की शिकायत पर जिलाधिकारी मुरादाबाद एवं जिलाधिकारी रामपुर ने मुरादाबाद जनपद के ग्राम गदईखेड़ा एवं भैय्यानगला के जनपद रामपुर के ग्राम बीसरा एवं नवाबगंज के साथ सीमा विवाद के निस्तारण के लिए अपने अपने जनपद के राजस्व और चकबंदी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की है। दोनों जनपदों की टीमें समन्वय स्थापित करके उक्त ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण / पैमाईश कर ग्रामों की सीमा निर्धारित करते हुए सीमा विवाद का निस्तारण करेंगी। उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद और उपजिलाधिकारी सदर रामपुर अपने अपने जिलों की टीमों के अध्यक्ष रहेंगे। विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने बताया मुरादाबाद जनपद के ग्राम

गदईखेड़ा एवं भैय्यानगला के जनपद रामपुर के ग्राम बीसरा एवं नवाबगंज के साथ सीमा विवाद के चलते कृषकों के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। दोनों जनपदों के राजस्व विभाग एवं चकबंदी विभाग की संयुक्त टीम की पैमाइश के बाद कुछ दिनों दोनों जनपदों के ग्रामों का सीमा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूर्व में मुरादाबाद जनपद के ग्राम भैयानगला एवं गदईखेड़ा की चकबंदी हुई, लेकिन चकबंदी विभाग द्वारा संपूर्ण किसानों के चकों का निस्तारण न करते हुए चकबंदी अधूरी छोड़कर समस्त राजस्व दस्तावेजों को तहसील सदर में जमा कर दिया गया था। इसलिए अभी तक सीमा विवाद का निस्तारण नहीं हो पाया था। इसलिए मैंने इस विषय को प्रतिनिहित विधायन समिति की बैठक में उठाया था और साथ ही मंडलायुक्त मुरादाबाद, उपनिदेशक चकबंदी मुरादाबाद मंडल, जिलाधिकारी मुरादाबाद और रामपुर को पत्र भी भेजा था।

धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और चुनाव आयोग से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है और याचिकाकर्ता को मामले में सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। याचिका में केंद्र सरकार को ऐसे निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिससे राजनीति में भ्रष्टाचार, जातिवाद और अपराधीकरण के खतरे कम हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि क्या एक न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने न्यायिक सेवा में आने से पहले ही बार में सात साल पूरे कर लिए हैं, रिक्त पद को देखते हुए वे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) बनने के हकदार हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर से इस मामले पर सुनवाई शुरू करेगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एम एम सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एस सी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ 23 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगी और तीन दिनों तक यानी 25 सितंबर तक दलीलें सुनेगी।

संविधान का अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है और इसमें लिखा है कोई व्यक्ति जो पहले से ही संघ या राय की सेवा में नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह कम

से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहा हो और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति के लिए उसकी सिफारिश की गई हो।

पीठ ने कहा कि उसे इस बात की जांच करनी होगी कि क्या बार में प्रैक्टिस और उसके बाद न्यायिक सेवा के संयुक्त अनुभव को पात्रता में गिना जा सकता है। उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत आने वाले एडीजे के पद निचले न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। ये पद वकीलों की सीधी भर्ती के माध्यम से भी भरे जाते हैं, जिनके पास बार में कम से कम सात वर्षों का अनुभव हो। अब मुद्दा यह है कि क्या कोई निचला न्यायिक अधिकारी भी वकीलों के लिए सीधी भर्ती कोटे के तहत एडीजे के पदों के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायिक अधिकारी या वकील या दोनों के रूप में उसके सात वर्षों के अनुभव को गिना जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित मुख्य परिसर में फोटो खींचने, सोशल मीडिया रील बनाने और वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 10 सितंबर को जारी एक सर्कुलर में, शीर्ष अदालत ने मीडियाकर्मियों को कम सुरक्षा वाले क्षेत्र लॉन में साक्षात्कार लेने और समाचारों का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि उच्च सुरक्षा क्षेत्र में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। आधिकारिक उपयोग को छोड़कर, वीडियोग्राफी, रील बनाने और फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैमरे, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक आदि उपकरण ले जाने पर भी उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगा। निर्देश में कहा गया है, किसी वकील, वादी, इंटर्न या लॉ क्लर्क द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित बार एसोसिएशन या संबंधित राय बार काउंसिल अपने नियमों और विनियमों के अनुसार उल्लंघनकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। इसमें कहा गया है कि अगर मीडियाकर्मी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में उनके जाने पर एक महीने के लिए प्रतिबंधित लगाया जा सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, सभी जजों ने बंद किया काम

नई दिल्ली । दिल्ली में बम की धमकी मिलने का सिलसिला जारी है. अब दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इसके बाद वकीलों और जजों में हड़कंप मच गया और सारी कोर्ट अचानक से उठ गई. हाई कोर्ट की ऑफिशियल मेल आईडी पर धमकी आई. ऐसे में हाई कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पुलिस टीम जांच में जुट गई.

जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने बम के धमकी भरे मेल को हॉक्स करार दिया. बम की धमकी भरे ईमेल में लिखा था कि, पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान-तमिलनाडु की मिलीभगत, जज रूम/कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं. दोपहर 2 बजे तक खाली करा दें. ईमेल में साफ चेतावनी दी गई कि आज शुक्रवार की नमाज के बाद बम धमाका होगा और जज चेंबर में विस्फोटक डिवाइस फट जाएगी. यह मेल पाकिस्तान और तमिलनाडु कनेक्शन की ओर इशारा करता है. इसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान की IED और कुछ लोकल नेटवर्क मिलकर पुराने 1998 पटना ब्लास्ट जैसे हमले को दोहराने की साजिश रच रहे हैं. मेल में शाह फैसल नाम के एक शख्स से आया. साथ ही मेल में हुस्न नेताओं और राजनीतिक समीकरणों का भी जिक्र था. मेल के मुताबिक पार्टी वारिसों को रोकने और बीजेपी-आरएसएस के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए आतंकवादी प्लान तैयार किया गया. मेल में एक मोबाइल नंबर और IED (बम) को डिफ्यूज करने की डीटेल तक लिखी गई. बम के डिफ्यूज कोड के लिए जो नाम और नंबर लिखा था, वो AIADMK की पूर्व संसद वी सत्यभामा का है. वी सत्यभामा 2014 से 19 तक तिरुपुर लोकसभा सीट से संसद रही हैं. इस धमकी भरे ईमेल के आते ही हड़कंप मच गया और कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. वकीलों और जजों को बाहर निकाला गया. वहीं बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच गया और आगे की जांच जुट गई. वकीलों का कहना था कि यहां कोई पैनिक नहीं है. जजों की चीफ जस्टिस के साथ मीटिंग भी हुई. दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली और परिसर खाली कराया गया. इससे पहले दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में बीते मंगलवार (9 सितंबर) को सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी. गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली के कई प्रतिष्ठित संस्थान, दफ्तर, स्कूल और कॉलेजों को बम की झूठी धमकियां मिल चुकी हैं. बाद में जांच के बाद पता चला कि यह धमकी झूठी थी.

उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा को झटका, शीर्ष कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक टाली

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। तीनों ने राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत याचिका लगाई थी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन्हें फाइलें बहुत देर से मिलीं। आरोपियों ने 2 सितंबर के दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें खालिद और इमाम सहित नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नागरिकों की ओर से प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिन लोगों की जमानत खारिज की गई, उनमें खालिद, इमाम, फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद शामिल हैं। एक अन्य अभियुक्त तस्लीम अहमद की जमानत याचिका 2 सितंबर को उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने खारिज कर दी थी।

कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए

उच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने और सार्वजनिक सभाओं में भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है। इसे स्पष्ट रूप से सीमित नहीं किया जा सकता, उसने यह भी कहा कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

आरोपी 2020 से जेल में

खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मास्टरमाइंड होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से यादा घायल हुए थे। सीएए और एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। आरोपी 2020 से जेल में हैं।

सुनील बंसल को बीजेपी में मिल गई ये बड़ी जिम्मेदारी, माना जाता है मोदी और अमित शाह का करीबी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा का संयोजक नियुक्त किया है। 2014 से भाजपा के एक प्रमुख नेता, बंसल ने इससे पहले लोकसभा चुनावों के लिए ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना में संगठनात्मक ज़िम्मेदारियाँ संभाली थीं, साथ ही उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक सचिव के रूप में भी कार्य किया था, जहाँ उन्होंने कई वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुनील बंसल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है। अब सेवा पखवाड़ा की ज़िम्मेदारी सौंपे जाने के बाद, बंसल इस महाअभियान की तैयारी के लिए देश

भर के भाजपा नेताओं के साथ कार्यशालाएँ आयोजित कर चुके हैं। यह अभियान 17 सितंबर (प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन) से 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती) तक चलेगा। भाजपा ने रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, माँ के नाम पर एक पेड़ पहल, और प्रदर्शनियों और संवाद कार्यक्रमों सहित कई तरह की गतिविधियों की योजना बनाई है। सुनील बंसल ने बताया कि राज्यों में 771 संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे, जिनमें दिव्यांग नागरिकों के साथ विशेष संवाद भी शामिल होंगे, जिसके दौरान सहायक उपकरण भी वितरित किए जाएँगे। मोदी विकास मैराथन 21 सितंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा 75 से ज़्यादा प्रमुख शहरों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी भाजपा सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में खेल महोत्सवों का आयोजन करेंगे। खेल महोत्सव के लिए पंजीकरण 29 अगस्त से शुरू हो गए हैं, और औपचारिक कार्यक्रम 21 सितंबर से शुरू होंगे। यह अभियान दिसंबर और जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव और भाजपा महासचिव सुनील बंसल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी घोषणा की कि 25 सितंबर (दीनदयाल उपाध्याय जयंती) से भाजपा आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत अभियान शुरू करेगी, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक के रूप में, सुनील बंसल वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। दिलचस्प बात यह है कि बंसल 2016 से भाजपा के साथ हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय संयुक्त संगठन सचिव के पद से मुक्त होने के बाद, उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठन सचिव नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी भाजपा को फिर से शीर्ष पर लाने का काफी श्रेय बंसल को जाता है।

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस-राजद को घेरा, बोले- राम विरोधी स्टालिन के साथ क्यों मंच साझा?

नई दिल्ली ।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बिहार में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को मंच देने पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर सवाल उठाए। ठाकुर ने स्टालिन पर भगवान राम का अनादर करने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विरोध करने का आरोप लगाया। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, भाजपा सांसद ने कहा कि वह व्यक्ति (तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन) जो भगवान राम को नहीं मानते, वह राम मंदिर निर्माण और अपने बेटे द्वारा सनातन के बारे में दिए गए बयानों के खिलाफ थे और उन्होंने सनातन का अपमान किया। कांग्रेस और राजद ने उन्हें अपने मंच पर जगह क्यों दी? बिहार की जनता यह जानना चाहती है। ठाकुर की यह आलोचना वरिष्ठ डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आई है। मुरुगन ने तमिलनाडु में विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह राय बिहार जैसा नहीं है और यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। वेल्लोर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मंत्री ने बिहार के साथ तीखी तुलना की और ज़ोर देकर कहा कि तमिलनाडु का शासन और नेतृत्व बिहार से अलग है। मुरुगन ने संवाददाताओं से कहा कि तमिलनाडु, बिहार नहीं है। तमिलनाडु एक ऐसा राय है जहाँ लोग जागरूक हैं। वहाँ का शासन यहाँ जैसा नहीं है; यहाँ हमारे पास थलपति का नेतृत्व है, और इस तरह की चालें तमिलनाडु में या हमारे नेता के साथ काम नहीं करेंगी। मंत्री की यह टिप्पणी मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चल रही चर्चा के जवाब में आई। बुधवार को, चुनाव आयोग (ईसी) ने सभी राय और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए उनकी तैयारियों का आकलन किया गया। यह इस वर्ष मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का तीसरा सम्मेलन था। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की उपस्थिति में किया।

दिल्ली में ऊंटों के जरिए शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने शराब तस्करी का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला उजागर किया है. पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के जंगलों के रास्ते ऊंटों के जरिए शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 42 शराब के डिब्बे और तीन ऊंट बरामद किए हैं. अधिकारियों के अनुसार, यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और शराब की अवैध खेप को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल करता था. उनका तरीका बेहद अनोखा था. आरोपियों ने चौकियों और गश्ती दलों से बचने के लिए कच्चे और सुनसान रास्तों का चुनाव किया. वे ऊंटों की पीठ पर शराब के डिब्बे लादकर जंगलों और अंधेरी पगडंडियों से शराब की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि तस्कर अक्सर रात के समय सक्रिय होते थे. ऊंटों पर रखे शराब के डिब्बे सामान्य नजर में दिखना मुश्किल होता था, जिससे उन्हें पकड़ना कठिन हो जाता था. यही वजह थी कि वे कई बार पुलिस और स्थानीय निगरानी से बचने में सफल हो जाते थे. हालांकि, पुलिस को लगातार मिल रही गुप्त सूचनाओं के आधार पर एक विशेष टीम बनाई गई. टीम ने तस्करों की गतिविधियों पर नजर रखी और सही समय पर कार्रवाई कर उन्हें धर दबोचा.